एनसीआरटीसी ने तैयार किया है दिल्ली-रुड़की रोड पर जोनल प्लान, आपत्तियों के निस्तारण के बाद पास होने को भेजा जाएगा

रैपिड रेल कॉरिडोर जोनल प्लान पर लगेगी मुहर

प्रोजेक्ट अपडेट

मेरठ, वरिष्ठ संवाददाता। रैपिड रेल कॉरिडोर को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस बनाने को एनसीआरटीसी द्वारा तैयार किए जोनल प्लान को मेडा ने पास करने के लिए शासन में भेज दिया है। मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक (सीटीसीपी) द्वारा जोनल प्लान पर मुहर लगाई जाएगी। इसके बाद जोनल प्लान पर मेडा, नागरिकों की आपत्ति आमंत्रित करेगा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद बोर्ड से पास करा लागू कर दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई ट्रांजिट ऑरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति के तहत बनाए जोनल प्लान से शहरवासी रैपिड रेल कॉरिडोर क्षेत्र में न केवल आवासीय के साथ कॉमर्शियल गतिविधियां कर सकेंगे बल्कि स्कूल, अस्पताल, रिजॉर्ट और कॉम्पलेक्स बना सकेंगे। जोनल प्लान में शामिल किए मिश्रित भू-उपयोग से दिल्ली-रुड़की रोड की रंगत बदल जाएगी। आने वाले समय में कॉरिडोर के दोनों ओर, रैपिड-मेट्रो स्टेशनों के आसपास का मेरठ गुरुग्राम और नोएडा की तरह नजर आएगा।

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के वीसी संजय कुमार मीना का कहना है कि रैपिड रेल कॉरिडोर को टीओडी नीति के तहत एनसीआरटीसी द्वारा तैयार किया जोनल प्लान शासन को भेजा है।

वहां से स्वीकृति के बाद इस पर नागरिकों की आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद इसे बोर्ड से पास करा लागू कर दिया जाएगा।

रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना जोनल प्लान के 9 जोन

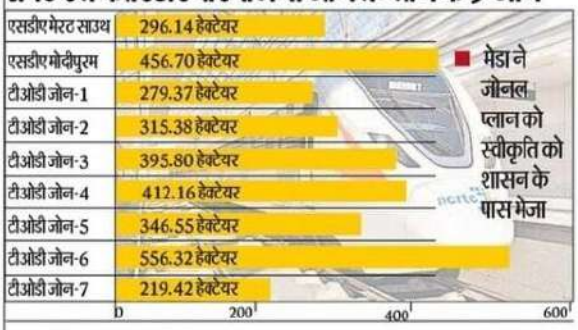

9 जोन में बांटा है रैपिड रेल कॉरिडोर

एनसीआरटीसी ने रैपिड रेल कॉरिडोर को 9 जोन में बांटकर जोनल प्लान तैयार किए हैं। कॉरिडोर के दोनों तरफ 500 मीटर और वाराें रैपिड स्टेशनों के दोनों तरफ 1.5 किमी तक के दायरे में विश्वस्तरीय आवासीय, व्यावसायिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

यह है टीओडी नीति

ट्रांजिट ऑरिएंटेड डेवलपमेंट नीति सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों जैसे रैपिड और मेट्रो रेल नेटवर्क के आसपास केंद्रित समुदायों के निर्माण पर केंद्रित है। यह शहरी नियोजन अवधारणा है जिसका उद्देश्य उच्च घनत्व, मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्र का विकास करना है ताकि पैदल चलना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना आसान हो सके। इस नीति के तहत बनने वाले जोन में आवासीय, व्यावसायिक, स्कूल, अस्पताल और कार्यालय शामिल होते हैं।

इन सुविधाओं का होगा विकास

रैपिड रेल कॉरिडोर के समानांतर आवासीय एवं कॉमर्शियल बहुमंजिला इमारतें, इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल, अस्पताल, रिजॉर्ट, क्लब, आईटी सेक्टर, कंपनियों के ऑफिस, वेलनेस हब, डाटा सेंटर, एम्यूजमेंट पार्क, कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, इंटर कॉलेज, डिस्पेंसरी, डायग्नोस्टिक सेंटर, लाइब्रेरी, बारातघर, सामुदायिक केंद्र, लाइब्रेरी का विकास किया जाएगा।

251 हेक्टेयर में औद्योगिक टाउनशिप बनेगी

मेरठ/गाजियाबाद। मोदीनगर के 251 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप बनेगी। इसे लॉजिस्टिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। मंगलवार को मेरठ मे मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई जीडीए बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक मे मोदीनगर के गांव सैदपुर हुसैनपुर डीलना में औद्योगिक टाउनशिप के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यहां 61.8457 हेक्टेयर सरकारी और 189.2478 हेक्टेयर निजी जमीन मौजूद है। यह क्षेत्र दिल्ली-मेरठ नॉर्दर्न एक्सप्रेसवे पर परतापुर बाइपास से करीब सात किमी दूर है। दिल्ली मेरठ रोड के भी पास है।

हस्तिनापुर नगर पंचायत होगा सोलर से रोशन

मेरठ, मुख्य संवाददाता। महाभारतकालीन हस्तिनापुर को गुजरात के मोढेरा ग्राम की तर्ज पर सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव है। राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह प्रस्ताव दिया है। डीएम से हस्तिनापुर नगर पंचायत क्षेत्र के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि केन्द्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से सोलर सिटी बनाने की योजना पर काम हो सके।

राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हस्तिनापुर नगर पंचायत के सोलर सिटी प्रोजेक्ट को लेकर डीएम और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) के निदेशक को पत्र लिखा है। उन्होंने डीएम से फोन पर वार्ता भी की है। कहा है कि केन्द्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से गुजरात के मोढेरा गांव पूरी तरह से सोलर विलेज में बदल दिया है। मोढेरा में घर, टीवी, फ्रिज और एसी जैसे सभी उपकरण सौर ऊर्जा से चलते हैं। मेरठ की हस्तिनापुर नगर पंचायत को भी इसी तरह सोलर सिटी बनाया जा सकता है। डीएम से हस्तिनापुर नगर पंचायत का कुल क्षेत्रफल, आबादी, घरों की संख्या, स्कूल-कालेज, अस्पताल, मंदिरों की संख्या आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

गुजरात का मोढेरा मॉडल 65 करोड़ का है

वाजपेयी ने गुजरात के मोढेरा मॉडल पर ₹65 करोड़ के खर्च की जानकारी दी है, जिसमें केंद्र सरकार और गुजरात सरकार ने 50% हिस्सेदारी साझा की है। योजना में छह मेगावाट का ग्राउंड-माउंटेड सोलर पीवी पावर प्लांट, 1297 घरों पर एक किलोवाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम, सरकारी भवनों पर 305 किलोवाट की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम आदि स्थापित किए गए हैं।